



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 765 राँची, शनिवार

2 कार्तिक, 1937 (श०)

24 अक्टूबर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 सितम्बर, 2015

1. उपायुक्त, बोकारो का पत्रांक-1475/स्था०, दिनांक-01 अक्टूबर, 2010
 2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-793, दिनांक 14 फरवरी, 2011; संकल्प सं०-4395, दिनांक 30 जुलाई, 2011; पत्रांक-370, दिनांक 12 जनवरी, 2013; पत्रांक-4539, दिनांक-21 मई, 2015 तथा पत्रांक-5564, दिनांक 23 जून, 2015
 3. श्रीमती राजबाला वर्मा, भा०प्र०से०, तत्कालीन प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-299, दिनांक 10 सितम्बर, 2012
 4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक-1893, दिनांक 10 अगस्त, 2015
-

संख्या- 5/आरोप-1-332/2014 का.-8297-- श्री जेवियर हेरेंज, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-706/03, गृह जिला-गुमला), सम्प्रति- निलंबित के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, चास की कार्यावधि में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1475/स्था0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं। श्री हेरेंज के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में निम्न आरोप हैं:-

“1984 सिख दंगे में मुआवजा भुगतान से संबंधित सरकारी निदेश पत्रांक-सं0यू0 13018/46/2005 दिनांक 16 जनवरी, 2006 से स्पष्ट है कि पूर्व में मुआवजा भुगतान किये गये लाभुकों को ही भुगतान किया जाना है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास श्री जेवियर हेरेंज ने गलत अभिलेख तैयार कर श्री सर्वजीत सिंह कलसी को रू0 16,30,000/- एवं स्व0 सरदुल सिंह कलसी (प्राप्तकर्ता श्री सर्वजीत सिंह कलसी) को रू0- 55,00,000/- का मुआवजा भुगतान किया। संबंधित अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि श्री कलसी को पूर्व में कोई भी भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में चास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। वास्तव में जिला नजारत शाखा से रू0 48,000/- का पूर्व में श्री कलसी को भुगतान किया गया था, अतः सरकारी निदेश के आलोक में रू0- 4,32,000/- का भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि रू0 71,30,000/- का भुगतान कर दिया गया। इसके लिए श्री हेरेंज प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।”

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-793, दिनांक 14 फरवरी, 2011 द्वारा श्री हेरेंज से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की दशा में विभागीय संकल्प सं0-4395, दिनांक 30 जुलाई, 2011 द्वारा श्री हेरेंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती राजबाला वर्मा, भा0प्र0से0, तत्कालीन प्रधान सचिव; खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री हेरेंज द्वारा समर्पित बचाव-बयान निम्नवत् है:-

(i) दिनांक 29 मार्च, 2007 को समिति की बैठक की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी को क्रमशः 16,30,000/- रू0 एवं 55,00,000/- रू0 भुगतान करने की अनुशंसा की गयी थी।

(ii) आरोप-पत्र में जिला नजारत शाखा से श्री कलसी को ₹0 48,000/- भुगतान करने की बात कही गयी है, इसकी जानकारी अनुमंडल कार्यालय को नहीं दी गयी थी।

(iii) जब जिला नजारत शाखा से ₹0 48,000/- का भुगतान श्री कलसी को कर दिया गया था तो फिर उपायुक्त कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-288, दिनांक 30 मार्च, 2007 में किस परिस्थिति में दिनांक 29 मार्च, 2007 के निर्णयानुसार श्री सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी को क्रमशः 1,63,000/- ₹0 एवं 5,50,000/- ₹0 की राशि पूर्व में स्वीकृत राशि के रूप में दिखलाया गया।

(iv) यदि जिला नजारत शाखा द्वारा ₹0 48,000/- की भुगतान किया गया था, तो जिला नजारत द्वारा इस बात को दिनांक 29 मार्च, 2007 की समिति की बैठक में उठाया जाना चाहिए था।

(v) उपायुक्त कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-288, दिनांक 30 मार्च, 2007 में दिनांक 29 मार्च, 2007 को हुई बैठक के एवज में पीडितों को राशि भुगतान हेतु विवरणी के साथ श्री हेरेंज को अभिलेख उपलब्ध कराया गया था, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2007 तक राशि की निकासी कर भुगतान करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया था।

(vi) दिनांक 31 मार्च, 2007 को अपर समाहर्ता, बोकारो के द्वारा भी दिनांक 29 मार्च, 2007 की बैठक में लिये गये निर्णय की विवरणी संलग्न करते हुए यह संसूचित किया गया कि चास अनुमंडल में कुल पाँच सिख परिवारों को मुआवजा भुगतान हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस हेतु उन्हें उक्त पत्र में निदेशित किया गया था कि मुआवजा का भुगतान अविलम्ब करने हेतु तिथि का निर्धारण कर संबंधित परिवारों एवं मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुए उन्हें भी अवगत कराया जाय। भुगतान से संबंधित पावती रसीद भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

(vii) उपायुक्त के आदेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के आधार पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा विवरणी में दर्शाये गये शुद्ध भुगतेय राशि यानी 16,30,000/- ₹0 एवं

55,00,000/- ₹0 का भुगतान क्रमशः श्री सर्वजीत सिंह कलसी एवं श्री सरदुल सिंह कलसी को किया गया।

(viii) प्रश्नगत व्यक्तियों के दावों के भुगतान हेतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी थी और न ही इनके भुगतान संबंधी प्रतिवेदन तैयार किया गया था। इसलिए इनके द्वारा कही भी अनियमितता नहीं की गयी।

श्री हेरेंज के विरुद्ध आरोप एवं इनके बचाव-बयान पर विचार करते हुए श्रीमती राजबाला वर्मा, भा0प्र0से0, तत्कालीन प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-299, दिनांक 10 मार्च, 2012 द्वारा श्री हेरेंज के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो इस प्रकार है:-

(i) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक-यू0-13018/46/2005 दिनांक 16 जनवरी, 2006 द्वारा 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अनुसार क्षतिग्रस्त रिहायशी संपत्तियों के लिए वास्तव में दी गयी राशि की 10 गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि दी जायेगी, इसमें से पहले से दी जा चुकी राशि कम कर दी जायेगी।

(ii) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निर्णय के आलोक में वर्ष 1984 सिख दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को पैकेज भुगतान संबंधी मामले पर विचार करने के लिए उपायुक्त, बोकारो के अध्यक्षता में दिनांक 29 मार्च, 2007 को बैठक আহूत की गयी थी, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, चास द्वारा 1984 सिख दंगे में घरेलू सामग्री/दुकान/व्यापार की क्षति से संबंधित छः आवेदकों की विवरणी प्रस्तुत की गयी।

(iii) इसमें श्री सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी को पूर्व में क्रमशः ₹0 1,63,000/- एवं ₹0 5,50,000/- राशि स्वीकृत किये जाने तथा पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए श्री सर्वजीत सिंह कलसी को ₹0 16,30,000/- एवं श्री सरदुल सिंह कलसी के मृत्योपरान्त श्री सर्वजीत सिंह कलसी को ₹0 55,00,000/- अनुदान राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गयी।

(iv) दिनांक 29 मार्च, 2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-285, दिनांक 30 मार्च, 2007 द्वारा सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची से वर्ष 1984 सिख दंगा पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को पैकेज भुगतान करने के लिए राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(v) तदुसार गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-180, दिनांक 30 मार्च, 2007 द्वारा वर्ष 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में उनके आश्रितों को पैकेज प्रदान करने के लिए बोकारो जिला को मो0 1,88,50,000/- रू0 आवंटन दिया गया।

(vi) उक्त के आलोक में उपायुक्त, बोकारो के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-288, दिनांक 30 मार्च, 2007 द्वारा वर्ष 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को अनुदान राशि भुगतान करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, चास को रू0 1,45,54,500/- राशि उप आवंटित करते हुए श्री जेवियर हेरेंज, अनुमंडल पदाधिकारी, चास को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया।

(vii) उपायुक्त, बोकारो के उप आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि इसमें किसी प्रकार की विसंगति/अनियमितता की सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(viii) उक्त के आधार पर श्री हेरेंज द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2007 को कोषागार से राशि की निकासी कर ली गयी तथा बगैर किसी सरकारी कर्मी के पहचान के दिनांक 13 अप्रैल, 2007 को श्री सर्वजीत सिंह कलसी को रू0 71,30,000/- का भुगतान कर दिया गया।

(ix) श्री हेरेंज का यह कथन कि प्रश्नगत व्यक्तियों के दावों के भुगतान हेतु न ही उनके द्वारा अनुशंसा की गयी है और न ही इसके भुगतान संबंधी प्रतिवेदन उनके द्वारा तैयार किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है।

(x) श्री सर्वजीत सिंह कलसी एवं श्री सरदुल सिंह कलसी को पूर्व में एक भी रूपया अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया था, परन्तु श्री हेरेंज द्वारा एक सुनियोजित साजिश के

तहत् जिला स्तरीय कमिटी के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर श्री सर्वजीत सिंह कलसी एवं श्री सरदुल सिंह कलसी को क्रमशः 16,30,000/- रू0 एवं 55,00,000/- रू0 अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान करने की सहमति प्राप्त की गयी तथा कोषागार से राशि की निकासी कर भुगतान भी किया गया।

(xi) इस प्रकार रुपये 71,30,000/- सरकारी राजस्व की क्षति के लिए श्री जेवियर हेरेंज पूर्णतः दोषी हैं। आरोप प्रमाणित होता है।

श्री हेरेंज के विरुद्ध प्राप्त आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त, श्री हेरेंज के बचाव बयान को अस्वीकार किया गया एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इनके विरुद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित पाया गया। इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित दण्ड संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक-370, दिनांक 12 जनवरी, 2013 द्वारा श्री जेवियर हेरेंज से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री हेरेंज के पत्र, दिनांक-26 फरवरी, 2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब तथा दूसरे पत्र, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 द्वारा पूरक जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी के पक्ष में कोई अनुशंसा नहीं की है। इन्होंने पैकेज भुगतान के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही के आलोक में निर्गत आवंटन आदेश का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि आवंटन आदेश के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, चास के पत्रांक-164, दिनांक 29 मार्च, 2007 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो के पत्रांक-136/रा0, दिनांक 29 मार्च, 2007 तथा जिला में आयोजित 29 मार्च, 2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दोनों अनुमंडलों को राशि आवंटित की गयी है। श्री हेरेंज का यह भी कहना है कि वस्तुतः सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी तथा उनके परिवार को 1984 के सिख दंगों में घरेलू सामग्री/दुकान/व्यापार की क्षति का आकलन उनके अनुमंडल पदाधिकारी, चास के पदस्थापन के पूर्व किया गया था। 1988 में तदेन भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास द्वारा क्षति आकलन प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया गया था एवं तत्कालीन

अनुमंडल पदाधिकारी, चास ने इस संबंध में अपर समाहर्ता, बोकारो से पत्राचार भी किया था। संभवतः इसी आकलन के आधार पर 29 मार्च, 2007 की बैठक में समिति द्वारा इन दोनों के पक्ष में मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गयी है। श्री हेरेंज ने अपने प्रथम उत्तर के अनुलग्नक-4 के रूप में रक्षित सिख दंगों में घरेलू सामग्री/दुकान/व्यापार की क्षति से संबंधित भुगतान की तुलनात्मक विवरणी को उद्धृत करते हुए कहा है कि विवरणी के क्रमांक-2 एवं 3 पर क्रमशः सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी का नाम अंकित है। इन दोनों के नाम के आगे स्तम्भ-7 में भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा आकलित राशि क्रमशः 1,63,000/- एवं 5,50,000/- का उल्लेख किया गया है। इस तुलनात्मक विवरणी से स्वतः स्पष्ट होता है कि इन दोनों के पक्ष में स्वीकृत मुआवजा राशि का आधार तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास द्वारा किया गया आकलन है न कि उनकी अनुशंसा। श्री हेरेंज ने 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र की कंडिका-IV का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार, "मृत्यु तथा चोट के लिए अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने संबंधी किसी भी नये दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। पहले अनुग्रह राशि प्राप्त कर चुके व्यक्ति ही बड़ी हुई अनुग्रह राशि के पात्र होने चाहिए तथापि यदि कोई लंबित अथवा ऐसे विवादित मामले हों, जिनपर आवश्यक सबूत/साक्ष्य के अभाव में निर्णय नहीं हुआ हो, तो ऐसे मामलों पर तभी विचार किया जा सकता है यदि उन्हें वाजिब दावों के रूप में अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है।" उक्त कंडिका के आधार पर श्री हेरेंज का कहना है कि 1988 में पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी, चास के पत्र तथा उक्त अवधि में कार्यरत भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास के क्षति आकलन प्रमाण-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी के दावों के आधार पर क्षति का अंतिम रूप से आकलन कर लिया गया था, परन्तु भुगतान नहीं हुआ था। जहाँ तक श्री सर्वजीत सिंह कलसी को 48,000/- ₹0 पूर्व में भुगतान किये जाने का प्रश्न है, यह उनकी जानकारी में नहीं था। जिला नजारत का दायित्व था कि बैठक में श्री कलसी को भुगतान राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करते। श्री हेरेंज के अनुसार स्वीकृत मुआवजा राशि से संबंधित आवंटन आदेश 31 मार्च, 2007 को निर्गत हुआ था। यदि उसी

दिन राशि की निकासी नहीं की जाती तो आवंटन व्ययगत हो जाता। उन्होंने उपायुक्त के आवंटन आदेश के आलोक में निकासी की है, इसलिए इसके लिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता है। पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति अलग बिन्दु है तथा राशि की निकासी अलग। इन दोनों को एकीकृत कर मात्र उन्हें दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है। पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता था, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते थे। समिति के अन्य सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक एवं अपर समाहर्ता होते थे। पुनर्वास पैकेज के लिए जिला स्तर पर अपर समाहर्ता, बोकारो को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। अल्पसंख्यक आयोग द्वारा श्री सर्वजीत सिंह कलसी को बोकारो जिला के समिति का मनोनीत सदस्य रखा गया था। स्पष्ट है कि पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति एक सामूहिक निर्णय था, जिसे एक समिति द्वारा लिया गया था। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। प्रश्नगत मामलों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी न तो समिति के सदस्य थे और न ही नोडल पदाधिकारी। श्री हेरेंज का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा प्रश्नगत मामले में भुगतान पैकेज की तुलनात्मक विवरणी पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य पदाधिकारी यथा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं अपर समाहर्ता के साथ-साथ जिला नजारत की भूमिका की जाँच करने का आदेश दिया गया है। जाँच पूर्ण होने पर स्पष्ट हो जायेगा कि वे इस मामले में दोषी नहीं हैं। इस मामले में न तो संबंधित लाभुक के पक्ष में उन्होंने अनुशंसा की थी और न ही उन्हें जिला नजारत द्वारा पूर्व भुगतान की जानकारी थी। बोकारो जिला प्रशासन या संचालन पदाधिकारी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अनुमंडल पदाधिकारी, चास के पदस्थापन अवधि में उन्होंने सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी के पक्ष में मुआवजा राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की है। उन्होंने संबंधित साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराने की माँग की थी जो संचालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि सभी मंतव्य एवं परामर्श अनुमान पर आधारित हैं। उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए साक्ष्य तो दूर परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है।

श्री हेरेंज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब एवं पूरक जवाब के की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्नवत् तथ्य प्रकाश में आये:-

(i) अपर समाहर्ता, बोकारो के ज्ञापांक-142, दिनांक 19 फरवरी, 2007 एवं ज्ञापांक-199, दिनांक 28 फरवरी, 2007 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, चास से अनुरोध किया गया कि दंगा पीड़ितों को प्रमाण-पत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने हेतु उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मामले से संबंधित आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य के आलोक में जाँचोपरान्त नियमानुरूप यथोचित कार्रवाई की जाय तथा अध्यक्ष, बोकारो दंगा पीड़ित एवं पुनर्वास समिति, बोकारो से प्राप्त अभ्यावेदन पर जाँचोपरान्त आवश्यकतानुसार राशि के साथ अविलंब प्रतिवेदन भेजा जाय, ताकि जिला स्तरीय समिति से पारित कराकर सरकार से राशि आवंटित कराने हेतु अनुरोध किया जा सके ।

(ii) संचिका में रक्षित अभिलेखों से स्पष्ट है कि इसके बाद 29 मार्च, 2007 को जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलायी गयी। बैठक की कार्यवाही एवं अनुमण्डल कार्यालय, चास से सम्बन्धित 1984 सिक्ख दंगे में घरेलू सामग्री/दुकान/व्यापार के क्षति से सम्बन्धित भुगतान की विवरणी को देखने से पता चलता है कि-

(क) स्तंभ-6 पर सिक्ख दंगे से सम्बन्धित दर्ज प्राथमिकी बालीडीह थाना काण्ड सं0-112/84 दोनों मामलों के लिए एक ही काण्ड संख्या बतायी गयी है ।

(ख) स्तंभ-7 पर सर्वजीत सिंह सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी को दंगे से हुई क्षति का आकलन/अनुमानित राशि क्रमशः 1,63,000/- एवं 5,50,000/- की राशि स्वीकृत दिखायी गयी है ।

(ग) स्तंभ-8 पर परन्तु पूर्व में भुगतान की गयी राशि शून्य अंकित है ।

(घ) स्तंभ-9 पर वर्तमान में शुद्ध देय राशि सरकारी नीति के अनुसार सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी के मृत्योपरान्त पुनः उनके पुत्र सर्वजीत सिंह कलसी को क्रमशः 16,30,000/- एवं 55,00,000/- दिखाई गई है ।

(ङ) स्तम्भ-12 एवं 13 दोनों में अनुमण्डल पदा० द्वारा अनुषंसित एवं मंतव्य के रूप में "Recommen" अंकित है और इस विवरणी पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर में आरोपी पदा० श्री हेरेंज (तदेन अनुमंडल पदाधिकारी, चास); अंचलाधिकारी, चास; अपर समाहर्ता, बोकारो; पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं उपायुक्त, बोकारो के हस्ताक्षर हैं ।

(iii) बैठक की कार्यवाही उपायुक्त, बोकारो के ज्ञापांक-283(I), दिनांक 31 मार्च, 2007 के अनुसार श्री सर्वजीत सिंह कलसी, चास एवं श्री सरदुल सिंह कलसी, चास को क्रमशः 16.30 लाख एवं 55.00 लाख देय राशि दिखाते हुए लिखा गया है कि उपर्युक्त सभी आवेदन के सम्बन्ध में जांच एवं अनुशंसा अनुमण्डल पदा०, चास से प्राप्त है । कार्यवाही की प्रति सभी संबंधित को सूचनार्थ भेजी गयी है ।

(iv) इस प्रकार उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि आरोपी पदा० श्री हेरेंज ने अंकित राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा की थी एवं उनके जाँच के आलोक में ही दि०-29 मार्च, 2007 को बैठक बुलायी गयी थी ।

आरोपी पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि सर्वजीत सिंह कलसी एवं सरदुल सिंह कलसी को 1984 सिक्ख दंगों में घरेलू सामग्री/दुकान/व्यापार की क्षति का आकलन उनके पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया था एवं इस सम्बन्ध में वर्ष 1988 में तदेन भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास द्वारा क्षति का आकलन प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया गया था। आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में जिन दस्तावेजों को आधार बनाया गया है, उनके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार हैं ;

(क) भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास द्वारा वर्ष 1988 में निर्गत दो प्रमाण-पत्र- श्री सरदुल सिंह कलसी, पिता स्व० विसुन सिंह कलसी सा० सर्वजीत इण्डस्ट्रीज बालीडीह, बी०एस०सिटी को दिनांक, 01 नवम्बर, 1984 को हुए सिक्ख दंगे में क्षति 5,50,000/- अनुमानित राशि

आंकी गयी है । पुनः दूसरे प्रमाण-पत्र श्री सर्वजीत सिंह कलसी पिता सरदुल सिंह कलसी, सा0 सर्वजीत इण्डस्ट्रीज बालीडीह, बी0एस0सिटी को दिनांक 01 नवम्बर, 1984 को हुए सिक्ख दंगे में क्षति 1,63,000/- अनुमानित राशि आंकी गयी है । इन दोनों प्रमाण-पत्रों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, चास के पत्रांक-1231, दिनांक 01 अगस्त, 1988 द्वारा क्षति की अनुमानित राशि श्री सरदार सरदुल सिंह कलसी के लिए 5,50,000/- तथा श्री सरदार सर्वजीत सिंह कलसी के लिए 1,63,000/- बताया गया है ।

(ख) आरोपी पदाधिकारी को तदेन भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास के दिए गये उक्त दो प्रमाण-पत्रों की जांच इस आलोक में करनी चाहिए थी कि सरदार सरदुल सिंह कलसी एवं श्री सर्वजीत सिंह कलसी पिता-पुत्र हैं और क्षति का आकलन एक ही प्रतिष्ठान सर्वजीत इण्डस्ट्रीज बालीडीह के लिए करते हुए पिता को 5.50 लाख एवं पुत्र को 1.63 लाख की क्षति की अनुमानित राशि बतायी गयी है ।

(ग) आरोपी पदाधिकारी को यह भी देखना था कि सम्बन्धित दंगे की प्राथमिकी दोनों पीडितों के लिए बालीडीह थाना काण्ड सं0-112/84 दर्ज करायी गयी है एवं प्राथमिकी में भुक्तभोगियों ने क्या क्षति दिखलायी है? संचिका में लगे प्राथमिकी की प्रति देखने से पता चलता है कि सरदुल सिंह कलसी ने उक्त प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें अन्य बातों के अलावे उन्होंने लिखा है कि 35 तोला सोना करीब 70,000/- (सत्तर हजार) रुपये के, नकद 19,000/- (उन्नीस हजार) रुपये जो बक्सा में रखा था, कपड़ा बिस्तर बर्तन कुल कीमत रुपये 40,000/- के प्लेट मशीनरी स्टील का मटेरियल करीब 1,00,000/- (एक लाख) रुपये से ऊपर का लूट कर ले गये । इससे पता चलता है कि कुल 2,29,000/- (दो लाख उनतीस हजार) रुपये की संभावित क्षति हुई थी परन्तु किसी भी सक्षम पदाधिकारी ने न ही इस दस्तावेज को देखा एवं न ही इसके आधार पर क्षति के आकलन का सत्यापन किया ।

(घ) संचिका के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि सर्वजीत सिंह कलसी का अलग से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था बल्कि उन्होंने अपने पिता द्वारा दर्ज प्राथमिकी बालीडीह थाना

कांड सं0-112/84 के आधार पर ही रू0 16,30,000/- (सोलह लाख तीस हजार) रुपये का मुआवजा प्राप्त कर लिया ।

समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री जेवियर हेरेंज, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास को असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 (7) के तहत प्रमाणित आरोपों हेतु बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया ।

तदुसार, विभागीय पत्रांक-4539, दिनांक-21.05.2015 तथा स्मार पत्रांक-5564, दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री हेरेंज को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव पर सहमति/असहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में आयोग के पत्रांक-1893, दिनांक 10 अगस्त, 2015 द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी है ।

दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री हेरेंज को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने के प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गयी है कि जितनी राशि का गलत भुगतान किया गया है, उसकी वसूली, भुगतान प्राप्त करने वाले एवं भुगतान करने वाले दोनों से किये जाने की कार्रवाई की जाय ।

तदुसार, श्री हेरेंज को संकल्प निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही, उपायुक्त, बोकारो से अनुरोध है कि गलत भुगतान प्राप्त करने वाले एवं भुगतान करने वाले दोनों से राशि की वसूली कर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।
